SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

देवरिया जनपद, उत्तर प्रदेश में कृषि विकास स्तर का स्थानिक प्रतिरूप

प्रज्ञा मिश्रा, पीएच–डी, भूगोल विभाग
राजकीय महाविद्यालय, इन्दूपुर, गौरीबाजार, देवरिया, रूद्रप्रयाग, उत्तराखंड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
प्रज्ञा मिश्रा, पीएच–डी
E-mail : pragyamishratiwari@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 09/05/2026
Revised on : 10/07/2026
Accepted on : 19/07/2026
Overall Similarity : 00% on 11/07/2026

Plagiarism Checker X - Report
Originality Assessment
0%
Overall Similarity

Date: Jul 11, 2026 (02:40 PM)
Matches: 0 / 3004 words
Sources: 0

Remarks: No similarity found, your document looks healthy.

Verify Report:
Scan this QR Code

शोध सार

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में सभी के लिए समुचित खाद्य आपूर्ति बनाए रखने हेतु सर्वाधिक महत्ता वाला क्षेत्र कृषि का विकास है। कृषि विकास का अभिप्राय परम्परागत पद्धति में परिवर्तन कर न्यून उत्पादकता से उच्च उत्पादकता युक्त वैज्ञानिक एवं वर्तमान प्रतिरुप प्रदान करना, साथ ही उत्पादित सामग्री का समान सामाजिक वितरण एवं पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने से है। अध्ययन क्षेत्र देवरिया जनपद उत्तर के विशाल मैदान के एक भाग सरयू पारीय मैदान में अवस्थित है। कृषि यहाँ के लोगों के जीविकोपार्जन का मूलाधार ही नहीं बल्कि उनकी जीवन पद्धति भी है, इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में कृषि विकास के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित सूचकों का चयन कर सांख्यिकीय विधियों के द्वारा क्षेत्र में कृषि विकास स्तर वाले प्रदेशों के निर्धारण का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द

भारत, जनसंख्या, कृषि, जीविकोपार्जन.

परिचय

संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य अधिकांश राष्ट्रों के अनुसंधान, नवोन्मेश, विकास तथा नीति से संबंधित कार्यक्रमों में आवश्यक बदलाव की अपेक्षा करता है। भारत जैसे कृषि आधारित देश मे सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि–नीतियों तथा उनका प्रभावी रूप से अनुपालन इत्यादि का पुनःअवलोकन करना आवश्यक है (टास रिपोर्ट, 2019)। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की केन्द्र बिन्दु व भारतीय जीवन की धुरी है। आर्थिक जीवन का आधार, रोजगार का प्रमुख स्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जन का माध्यम होने के कारण कृषि को देश की आधारशिला कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी सम्बन्ध में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन का कहना है कि यदि कृषि की दुर्गति होती है और गरीबी एवं भुखमरी लम्बे समय तक विद्यमान रहती है तो देश में कभी शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। फसल व पशुपालन, मत्स्यपालन, वानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण समेत कृषि रोजगारपरक विकास

को प्रोत्साहित करता है। यह एक और वजह है जिसकी खातिर कृषि पुर्नजागरण को सबसे अधिक तवज्जो मिलनी चाहिए (स्वामीनाथन, 2007)। कृषि में हुई प्रगति स्वतन्त्र भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कृषि में यह प्रगति कृषि के अन्तर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र सम्मिलित कर, सिंचाई सुविधा, जल प्रबन्धन, उच्च किस्म के बीजों एवं उर्वरकों के प्रयोग तथा बेहतर कृषि तकनीक के कारण सम्भव हुई है (अवाटे एवं टोडकारी, 2012)। वर्तमान में भारत एक अन्न आयातक राष्ट्र से न सिर्फ खाद्यान्न पर पूरी तरह आत्मनिर्भर राष्ट्र बन चुका है बल्कि पर्याप्त मात्रा में भविष्य के लिए भण्डारण भी करता है। भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सर्वाधिक भाग (लगभग 22 प्रतिशत) कृषि व सहायक क्रिया–कलापों से आता है। कृषि ही भारत के लगभग दो–तिहाई कार्यशील जनसंख्या के लिए जीविका का स्रोत है (दूबे, 2011)। अतः कृषि में विकास के परिणामस्वरूप आय में वृद्धि होती है जिसका परिणाम है कि अन्ततः ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता कम होती है (राधाकृष्णन, 2002)। अतः कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाय तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी (सिंह, 2007)। कृषि के महत्व को देखते हुए ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में कमजोरियों को दूर करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है तथा देश के समावेशी विकास में कृषि को महत्वपूर्ण स्थान दिया है (सिंह, 2007)।

स्पष्ट है कि कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अतः इस क्षेत्र में तीव्र वृद्धि के द्वारा ही देश की सामाजिक–आर्थिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है (मुहम्मद, मुनीर एवं रहमान, 2007)। यही कारण है कि आर्थिक विकास सम्बन्धी योजनाओं में कृषि क्षेत्र का आधारभूत स्थान होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही कृषि को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता रहा है तथा इन योजनाओं में कृषि क्षेत्र को महत्व प्रदान करते हुए कृषि विकास हेतु दो रणनीतियाँ सुझायी गयी हैं– (अ) कृषि सम्बन्धी लागत पर सब्सिडी प्रदान करना, तथा (ब) कृषि सम्बन्धी आगत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करना (प्रसाद, 2006)।

इन रणनीतियों के द्वारा भारत में कृषि विकास के दो मुख्य उद्देश्यों को पूरा करना था। प्रथम, आर्थिक उद्देश्य जिसके अन्तर्गत कृषि के द्वारा अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करना तथा उससे औद्योगीकरण को भी सामर्थ्य प्रदान करना तथा द्वितीय, सामाजिक उद्देश्य के अन्तर्गत भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में प्रादेशिक विभिन्नता को दूर करना। इसी को आधार मानते हुए अनेक विकास कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है (हल्दर एवं दास, 2010)।

अध्ययन क्षेत्र भी एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। कृषि यहां के लोगों के जीविकोपार्जन का मूलाधार ही नहीं बल्कि उनकी जीवन पद्धति भी है इसलिए आवश्यक हो जाता है कि कृषि से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों का विश्लेषण कर भविष्य में कृषि विकास के नियोजन हेतु वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किये जा सकें।

अध्ययन क्षेत्र

देवरिया जनपद उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरी–पूर्वी सीमावर्ती भाग में मध्य गंगा मैदान के उपजाऊ भाग सरयूपारीय मैदान में अवस्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार $26^{0}7'$ उत्तर से $26^{0}44'$ उत्तर तथा देशांतरीय विस्तार $83^{0}30'$ पूर्व से $84^{0}15'$ पूर्वी देशांतर के मध्य है। जनपद का कुल क्षेत्रफल 2538 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 5 तहसील, 16 विकास खण्ड एवं 176 न्याय पंचायत आते हैं। देवरिया जनपद उत्तर में कुशीनगर, पूर्व में गोपालगंज और सीवान (बिहार राज्य), दक्षिण में मऊ और बलिया तथा पश्चिम में गोरखपुर जनपद से घिरा है। घाघरा, राप्ती और छोटी गंडक इस जनपद की मुख्य नदियां हैं।

जनगणना 2011 के अनुसार देवरिया जनपद की सम्पूर्ण जनसंख्या 3100946 है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 90.1 प्रतिशत है। जनपद की कुल कार्यशील जनसंख्या 28.54 प्रतिशत है जिसमें 49.9 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। यहां का सामान्य जनघनत्व 1069 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के औसत से अधिक है। अतः स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है जिसकी अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है और मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर है। जनपद की कुल साक्षरता 75.53 प्रतिशत है।

अध्ययन क्षेत्र गंगा मैदान का एक भाग है जो हिमालय से निकलने वाली घाघरा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए उपजाऊ कांप मिट्टी के गहरे निक्षेपण से बना है जिसकी औसत गहराई 3000 मीटर से 8000 मीटर के बीच मानी जाती है। ओल्डहम के अनुसार मैदान की औसत गहराई 5000 मीटर है। भूगार्भिक दृष्टिकोण से इस मैदान का निर्माण काल प्लीस्टोसीन तथा आधुनिक युग (होलोसीन) माना जाता है (गजेटियर, 1988)।

उच्चावच के दृष्टिकोण से क्षेत्र का सम्पूर्ण भाग लगभग समतल है जो केवल बीच–बीच में नदी घाटियों तथा कुछ बालू के कटकों के द्वारा ही कहीं–कहीं भंगित दिखाई देता है। क्षेत्र का सामान्य ढाल उत्तर–पश्चिम से दक्षिण–पूर्व दिशा की ओर

है। जनपद का उत्तरी भाग मुख्य रूप से बांगर मैदान है जहां बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं जा पाता है। जनपद के दक्षिणी भाग में राप्ती और घाघरा नदियों के सहारे नए जलोढ़ मिट्टी की पतली पट्टी मिलती है जिसे स्थानीय रूप से कछार कहा जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैः

- जनपद में कृषि विकास के स्तर को ज्ञात करना।
- कृषि विकास में भिन्नता की व्याख्या करना।
- कृषि विकास को प्रभावित करने वाले जनांकिकीय आर्थिक एवं सामाजिक कारकों की व्याख्या करना है।

विधितन्त्र

प्रस्तुत शोधपत्र पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। कृषि विकास सम्बन्धी सभी आँकड़े विकासखण्डवार संकलित किए गए हैं। अध्ययन हेतु जिले के सभी 16 विकासखण्डों को कृषि विकास स्तर के निर्धारण हेतु कृषि घटक के विभिन्न चयनित चरों को' स्कोर विधि के आधार पर समान इकाई के मान को जोड़कर तथा उसे 15 (चरों की कुल संख्या) से विभाजित कर संयुक्त सूचकांक प्राप्त किया गया। पुनः इन सूचकांकों को वर्गीकृत कर उच्च, मध्यम और न्यून कृषि विकास स्तर प्रदेशों का निर्धारण किया गया है।

कृषि विकास स्तर

किसी प्रदेश की आर्थिक सम्पन्नता एवं समृद्धि के लिए कृषि विकास आवश्यक तथ्य है। यह तथ्य तब और अधिक प्रासंगिक हो जाता है जब उस प्रदेश की 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि के परम्परागत तरीकों द्वारा ही कृषि कार्य में लगी हो तथा वहां कोई औद्योगिक आधार भी उपस्थित न हो (मिश्रा, 1986)। अतः कृषि देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, उनके स्तर को ऊँचा उठाने तथा उसमें संतुलन स्थापित करने में सहायक है। कृषि विकास का अभिप्राय परम्परागत पद्धति में परिवर्तन कर न्यून उत्पादकता से उच्च उत्पादकता युक्त वैज्ञानिक प्रतिरूप प्रदान करना, साथ ही उत्पादित सामग्री का समान सामाजिक वितरण तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने से है (गोले, 2007)। अतः कृषि विकास का सर्वप्रमुख उद्देश्य कृषि आगत में वृद्धि कर तीव्र दर से बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न की आपूर्ति की जा सके (श्रीवास्तव एवं सिह, 2010)।

अध्ययन क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। अतः यह आवष्यक हो जाता है कि कृषि से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों का विश्लेषण कर भविष्य में कृषि विकास के नियोजन हेतु वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किए जा सकें। जनपद में भूमि उपयोग प्रतिरूप के अन्तर्गत वन क्षेत्र, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि योग्य बेकार भूमि तथा शुद्ध कृषित भूमि का अध्ययन किया गया है। चूंकि क्षेत्र की जनसंख्या पूरी तरह कृषि पर ही निर्भर है तथा कृषि हेतु भूमि में और अधिक विस्तार की भी सम्भावना कम है अतः जनसंख्या के भरण–पोषण हेतु भूमि उपयोग क्षमता में वृद्धि ही एकमात्र उपाय है। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में धरातलीय समानता तथा उपजाऊ मृदा के कारण लगभग सभी प्रकार की फसलें बोयी जाती हैं, परन्तु स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक तथा अवस्थापनात्मक सुविधाओं में अन्तर के कारण भिन्न–भिन्न प्रकार की फसलें उगायी जाती हैं। क्षेत्र में खरीफ फसलों के अन्तर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंगफली, गन्ना, उर्द आदि फसलें तथा रबी फसलों के अन्तर्गत गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, सूरजमुखी, आलू आदि फसलें बोयी जाती हैं। प्रायः फसलों को दूसरी फसलों के साथ संयोजित कर उत्पन्न किया जाता है जिसे शस्य संयोजन कहते हैं। जनपद में मुख्यतः चावल–गेहूँ तथा गेहूँ–चावल का शस्य संयोजन क्षेत्र मिलता है जिससे भूमि पर जनसंख्या का दबाव तथा खाद्यान्न पर पूरी निर्भरता ज्ञात होती है। जनपद में एक फसल वर्ष में एक कृषि क्षेत्र में उगायी जाने वाली फसलों की संख्या के आधार पर गणना करने पर कुल शस्य गहनता 164 प्रतिशत प्राप्त हुई है परन्तु इसका क्षेत्रीय वितरण विषमतापूर्ण है जिसका कारण प्राकृतिक दशाओं की अनुकूलता तथा कृषि सम्बन्धी अवस्थापनात्मक सुविधाओं की उपस्थिति है। कृषि प्रधान क्षेत्र में तीव्र दर से बढ़ती जनसंख्या हेतु खाद्यान्न आपूर्ति तथा कृषि हेतु उपलब्ध भूमि का प्रयोग पूरी सीमा तक कर लेने के बाद कृषि उत्पादकता बढ़ाना ही सर्वप्रमुख उपाय है।

कृषि उत्पादन का स्तर विविध अवस्थापना तत्वों से प्रभावित एवं निर्धारित होता है जिनमें सिंचाई की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनपद में शुद्ध कृषित भूमि का लगभग 84 प्रतिशत भाग सिंचित क्षेत्र के रूप में सम्मिलित हैं परन्तु इसके क्षेत्रीय वितरण में पर्याप्त विषमता मिलती है। जनपद में विभिन्न स्रोतों द्वारा कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है जिनमें नलकूप, नहर, कुंए, तालाब आदि मुख्य हैं।

अध्ययन क्षेत्र में कृषि लोगों के जीवन का मूलाधार है। यह क्षेत्र समतल उपजाऊ मैदानी भाग में बसा हुआ है जो कृषि के लिए सर्वथा अनुकूल है। इसी के साथ यह क्षेत्र उच्च जनघनत्व वाला है तथा अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है जिससे कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक जन दबाव है (सिद्दीकी, 2010)। अतः यह आवश्यक है कि कृषि विकास का विश्लेषण कर भविष्य में कृषि विकास के नियोजन हेतु वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किए जा सके। कृषि विकास से सम्बन्धित उन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन में कृषि विकास के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित सूचकों का चयन कर अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास स्तर निर्धारण करने का प्रयास किया गया है। कृषि विकास स्तर के निर्धारण हेतु निर्धारित प्रमुख चर अग्रांकित हैंः

1. शुद्ध कृषि भूमि का प्रतिशत।
2. दो फसली भूमि का प्रतिशत।
3. शस्य गहनता।
4. सिंचाई गहनता।
5. सिंचित भूमि का प्रतिशत।
6. प्रति लाख जनसंख्या पर राष्ट्रीय बैंक शाखाओं की संख्या।
7. प्रति लाख जनसंख्या पर ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या।
8. प्रति लाख जनसंख्या पर प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति की संख्या।
9. प्रति दस हजार हेक्टेयर शुद्ध कृषि भूमि पर ग्रामीण गोदामों की संख्या।
10. प्रति दस हजार हेक्टेयर शुद्ध कृषि भूमि पर कृषि सेवा केन्द्रों की संख्या।
11. प्रति दस हजार हेक्टेयर शुद्ध कृषि भूमि पर कीटनाशक विक्रय केन्द्रों की संख्या।
12. प्रति दस हजार हेक्टेयर शुद्ध कृषि भूमि पर बीज विक्रय केन्द्रों की संख्या।
13. प्रति दस हजार हेक्टेयर शुद्ध कृषि भूमि पर उर्वरक विक्रय केन्द्रों की संख्या।
14. कुल आबाद ग्रामों में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत।
15. कृषि उत्पादकता।

उपर्युक्त चयनित चरों को स्कोर विधि के आधार पर समान इकाई के मान को जोड़कर तथा उसे 15 (चरों की कुल संख्या) से विभाजित कर संयुक्त सूचकांक प्राप्त किया गया (तालिका 1)।

स्कोर की गणना निम्न सूत्र की सहायता से की गयी हैः

$$\text{स्कोर} = \frac{Xi - X}{SD}$$

जहाँ, Xi= चर
X = चर का औसत
SD= चर का मानक विचलन

पुनः Z स्कोर के संयुक्त सूचकांक के आधार पर सम्पूर्ण जनपद को उच्च, मध्यम तथा निम्न श्रेणी के कृषि विकास स्तर में विभाजित किया गया है जो तालिका 2 तथा चित्र 1 में दृष्टव्य है।

तालिका 1: देवरिया जनपद में विकासखण्डवार कृषि विकास स्तर का समंक सूचकांक

क्रम संख्या	विकास खण्ड	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	समंक सूचकांक
01	गौरी बाजार	0.58	1.76	0.1	1.76	0.1	-1.34	-0.54	-0.79	-0.38	-0.22	0.54	1	1.07	0.15	-0.69	0.21
02	बैतालपुर	1.34	0.32	0.79	0.32	-0.72	0.39	-0.24	-1.08	-0.37	0.3	1.82	1.71	1.81	0.46	2.23	0.5
03	देसई देवरिया	0.45	0.94	0.9	0.94	-0.83	-0.76	1.11	-1.02	1.24	-0.2	0.58	0.03	-0.09	-2.33	-0.46	-0.25
04	पथरदेवा	0.63	0.76	1.3	0.76	2.38	-1.06	2.99	-1.05	-0.08	-0.11	0.25	-0.29	-0.32	-0.79	-0.86	0.22
05	रामपुर कारखाना	0.01	-2.29	1.3	-2.29	0.83	-0.94	-0.4	-0.51	-0.16	-0.14	-0.12	0.07	-0.02	-1.01	-1.08	-0.45
06	दवरिया सदर	0.85	0.59	1.3	0.59	0.98	-0.55	-1.09	-0.27	1.22	-0.64	0.43	0.96	1.07	1.23	2.07	0.58
07	रुद्रपुर	0.57	-0.36	1.28	-0.36	0.94	-0.1	0.12	0.55	-1.2	3.63	-1.14	-1.11	-1.1	1.87	0.52	0.2
08	भलुअनी	0.51	0.04	-0.77	0.04	-0.97	-0.25	0.01	0.65	-0.21	-0.77	-0.88	-1.15	-1.14	0.1	1.18	-0.24
09	बरहज	-1.8	-0.79	-0.51	-0.79	-0.54	1.79	-1.3	0.18	0.31	-0.37	0.1	1	0.99	-0.23	-0.41	-0.16
10	भटनी	0.06	0.5	-0.29	-0.5	-0.52	2.02	-0.64	0.99	1.09	-0.68	-0.55	-0.25	-0.32	-0.75	-0.83	-0.11
11	भाटपार रानी	0.77	-0.48	-0.8	-0.48	-0.64	0.96	-0.61	0.03	0.1	-0.16	-0.48	-0.79	-0.84	0.01	-0.52	-0.26
12	बनकटा	0.67	-0.39	-0.47	-0.38	-0.06	-0.1	0.18	-0.27	-0.21	-0.22	-0.59	-0.07	-0.13	0.31	-0.67	-0.16
13	सलेमपुर	0.33	-1.4	0.5	-1.4	0.13	1.34	-0.95	1.66	1.22	-0.31	2.33	0.5	0.51	1.42	0.3	0.41
14	भगलपुर	0.46	1.51	1.3	1.5	1.23	-0.87	0.7	1.59	1.78	-0.55	0.29	0.96	0.96	-0.51	0.06	0.69
15	लार	-2.69	-0.08	-0.61	-0.11	-0.66	0.05	0.42	1.14	0.36	-0.24	-1.21	-0.22	-0.28	0.62	0.05	-0.23
16	तरकुलवा	-0.35	0.37	-1.93	0.39	-1.64	-0.58	0.23	-1.83	-2.24	0.67	-1.36	-2.36	-2.18	-0.56	-0.91	-0.95

*(**स्रोत**: द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर व्यक्तिगत गणना)*

तालिका 2: देवरिया जनपद में कृषि विकास स्तर

कृषि विकास स्तर	कृषि विकास स्तर का समंक सूचकांक	विकासखण्ड
निम्न	$<\overline{X}-1\sigma$ (<-0.42)	भटनी, बरहज, बनकटा, लार, भलुअनी, भाटपार रानी, देसही देवरिया,
मध्यम	$\overline{X}\pm1\sigma$ (-0.42-+0.42)	रामपुर कारखाना, तरकुलवा, रूद्रपुर, गौरीबाजार, पथरदेवा, सलेमपुर
उच्च	$>\overline{X}+1\sigma$ (>+0.42)	बैतालपुर, देवरिया सदर, भागलपुर

*(**स्रोत**: द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर परिकलित)*

उच्च कृषि विकास स्तर

उच्च कृषि विकास स्तर के अन्तर्गत जनपद के उत्तरी भाग में स्थित बैतालपुर, देवरिया सदर तथा दक्षिणी भाग में स्थित भागलपुर विकासखण्ड सम्मिलित हैं। इन विकासखण्डों में उच्च कृषि विकास स्तर का कारण इनकी अवस्थिति है अर्थात् जनपद मुख्यालय की समीपता के कारण विकास से सम्बन्धित सभी सुविधाओं की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। इसी के साथ ये क्षेत्र अन्य अवस्थापनात्मक सुविधाओं जैसे– कृषि नवाचार का अपेक्षाकष्त अधिक प्रयोग, सिंचाई की सुविधा, परिवहन के साधनों की सुलभता से भी लाभान्वित हैं।

मध्यम कृषि विकास स्तर

जनपद में कृषि क्षेत्र में मध्यम विकास स्तर के अन्तर्गत उत्तरी–पूर्वी भाग में स्थित रामपुर कारखाना, तरकुलवा, पथरदेवा, पश्चिमी भाग में गौरीबाजार तथा दक्षिणी भाग में स्थित सलेमपुर तथा रूद्रपुर विकासखण्ड सम्मिलित हैं। राप्ती नदी के बाढ़ग्रस्त एवं कछारी मिट्टी वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां कृषि का अपेक्षाकृत कम विकास पाया जाता है।

निम्न कृषि विकास स्तर

कृषि क्षेत्र में निम्न विकास स्तर के अन्तर्गत उत्तरी भाग में स्थित देसही देवरिया तथा दक्षिणी भाग में स्थित भलुअनी, भटनी, भाटपार रानी, बनकटा, लार तथा बरहज विकासखण्ड सम्मिलित हैं। यहां कृषि का निम्न विकास स्तर पाए जाने का मुख्य कारण प्राकृतिक दशाओं की प्रतिकूलता (बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, अनुपजाऊ मिट्टी), सिंचाई के साधनों की कमी, परम्परागत कृषि पद्धति, परिवहन के साधनों की कमी आदि है। अतः इन क्षेत्रों में कृषि विकास स्तर को ऊँचा उठाने के लिए कृषि सम्बन्धी अवस्थापनात्मक सुविधाओं को मुहैया कराना अति आवश्यक है।

चित्र 1

देवरिया जनपद

कृषि विकास–स्तर

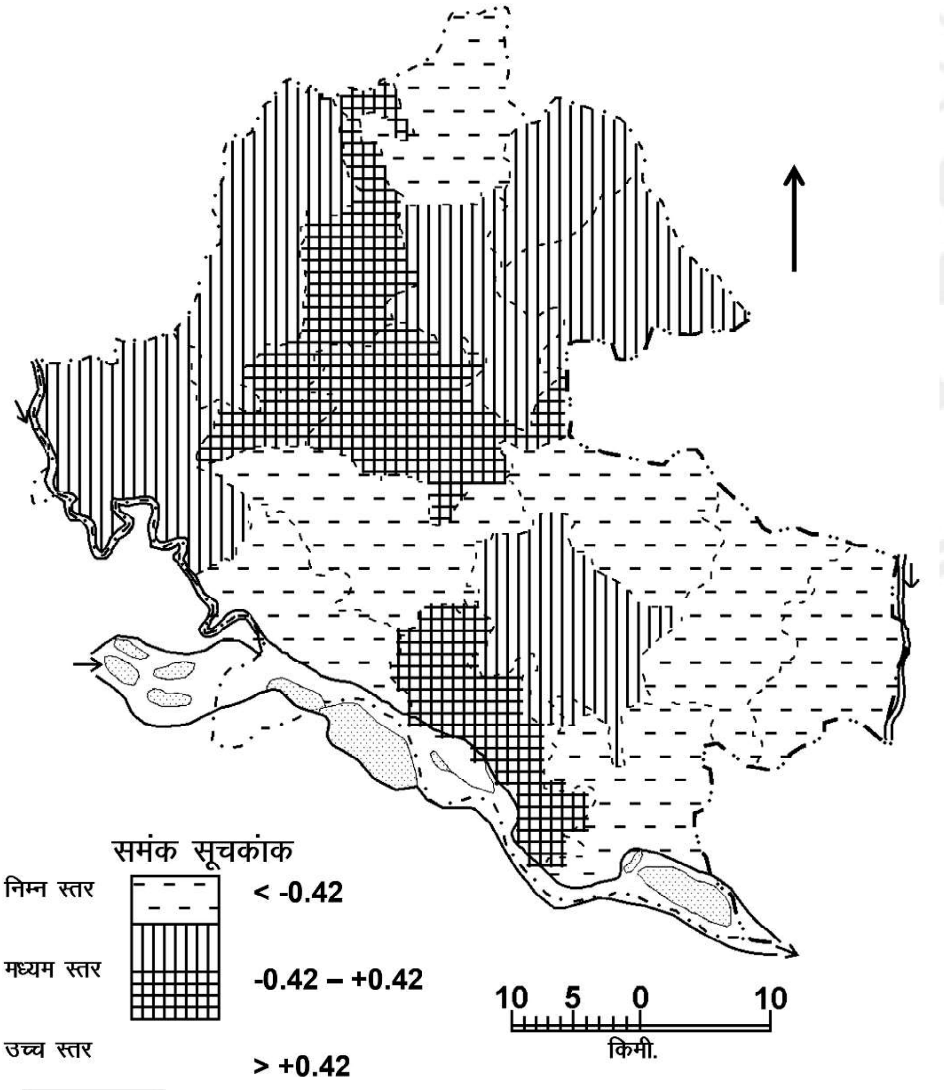

निष्कर्ष

कृषि अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीणों की आजीविका का मूलाधार होने के साथ–साथ उनकी आर्थिक सुदृढ़ता का सबल स्रोत भी है। अतः कृषि से सम्बन्धित विभिन्न प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं का उचित निराकरण अति आवश्यक है। क्षेत्र में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को देखते हुए कृषि योग्य बेकार भूमि को विभिन्न उपायों द्वारा कृषि हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है जिससे खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है परिणामस्वरूप लोग कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं की ओर उन्मुख हो रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि में नियन्त्रण के लिए साक्षरता एवं सामाजिक जागरूकता होना अति आवश्यक है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु सिंचाई सुविधाओं का विकास, कृषि सम्बन्धी अवस्थापनात्मक सुविधाओं

की वृद्वि, उच्च प्रजाति वाले बीजों का विकास स्थानीय भौतिक एवं सामाजिक–आर्थिक दशाओं के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। कृषि हेतु ऋण की सुविधाओं तक कृषकों की सरलता से पहुंच बनानी चाहिए जिससे कृषि में रूकावटों का सामना न करना पड़े। पूर्वांचल के इस पिछडे जिले में बिना कृषि के आधुनिकीकरण किए विकास की कल्पना करना एक दिवास्वप्न है। कृषि के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न सेवाएं सृजित करना तथा क्षेत्र के उत्पादों को बाजार प्रदान करना तथा नगरोन्मुख प्रवास की प्रवृत्ति को नियन्त्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अतः जनपद में कृषि क्षेत्र एक ऐसा अग्रणी क्षेत्र है जिसके पुनरावलोकन तथा पुनर्खोज करने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि परंपरागत कृषि पद्धतियों से समकालीन कृषि व्यवसाय पद्धतियों की ओर बढते हुए कृषि में रूपान्तरण कर क्षेत्र का समेकित विकास कर सकें।

संदर्भ सूची

1. Awate, S.J. and G.U. Todkari (2012) Agriculture Productivity in Solapur District of Maharashtra: A Geographical Analysis, *International Journal of Agriculture Sciences,* Vol. 4, Issue 2, p. 186-189
2. Dubey, Manish (2011) *Problems of Agricultural Growth in India,* Cyber Tech Publications, New Delhi, p. 11-41
3. Gazetteer of India (1988) Uttar Pradesh, Deoria District, Allahabad, p.45-55
4. Halder, Jadab Chandra and Pannalal Das (2010) The Changing Pattern of Basic Inputs and Their Impact on Crop Productivity in Paschim Medinipur District, West Bengal, *Geographical Review of India,* Vol. 72, No. 1, March, p. 91-105
5. Mishra, R.P. (1986) *Towards a Composite Approach to Agricultural Development, cited in,* P.S. Tiwari, Agricultural Geography, Heritage Publishers, New Delhi, p. 289-301
6. Mohammad, Ali, Abdul Munir and Rehman, Hifzur (2007) *Fifty Years of Indian Agriculture,* Vol.1, Concept Publishing Company, New Delhi, p. 11-22
7. Prasad, C.S. (2006) *Sixty Years of Indian Agriculture 1947 to 2007,* New Century Publications, New Delhi, p. 7-33
8. Radhakrishna, R. (2002) Agricultural Growth, Employment and Poverty: A Policy Perspective, *Economic and Political Weekly,* Vol.37, No.3, p. 243-50
9. Srivastava, Shweta and B.N. Singh (2010) *Agricultural Productivity and Level of Agricultural Development in Azamgarh District, Uttar Pradesh,* N.G.J.I., Vol. 56, pt. 2 & 4, Sept-Dec., p. 81-92
10. Siddiqui, Ahmad Mujtaba; Ali, Mohammad and Bushra, Iqrar (2010) *Problems and Prospects of Agricultural Development and Food Security in Middle Ganga Plain,* N.G.J.I., Vol. 56, pt. 1, March, p. 43-50
11. जिला सांख्यिकीय पत्रिका–2000 एवं 2015
12. स्वामीनाथन, एम. एस. (2007) कृषि क्षेत्र में व्यय एवं परिणाम, *योजना,* अंक–2, मई, पृ. 7–8।
13. सिंह, पी. के. (2007) जैविक कृषि की समस्याएं एवं सम्भावनाएं : गोरखपुर जनपद (उ. प्र.) का एक प्रतीक अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, दी.द.गो.वि., गोरखपुर, पृ. 111।
14. सिंह, मनमोहन (2007) कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना प्राथमिकता वाले क्षेत्र, *योजना,* अंक–1, अप्रैल, पृ. 7–11।
15. टास रिपोर्ट (2019) *सुरक्षित एवं सतत् कृषि के लिए नीतियों एवं कार्य योजना पर एक प्रतिवेदन,* भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर, नई दिल्ली।

****